

भूकंप- ऐसी आपदा जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती

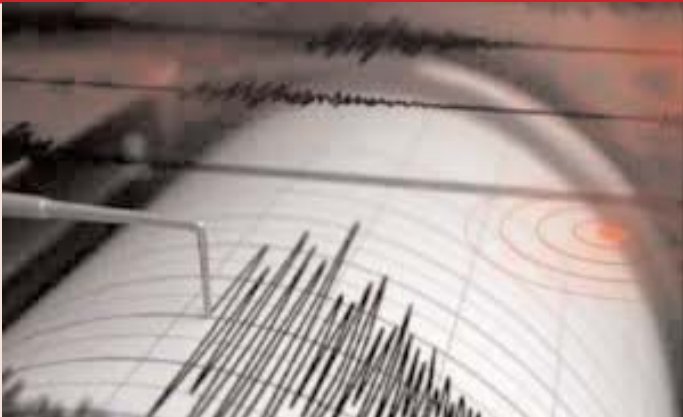
जापान के व्यूशू द्वीप पर फिर आया भूकंप। अभी तक जान माल की हानि की कोई खबर नहीं। म्यांमार में आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 3000 के पार। थाईलैंड में भी आए भूकंप के झटके। ये समाचार हैं जो पिछले कुछ दिनों से सुर्खियां बने हुए हैं। यह एक कटु सत्य है कि भूकंप जैसी आपदा का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकाला जा सका। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो मानव सभ्यता के लिए हमेशा से एक रहस्य और चुनौती बनी हुई है। जब भी प्राकृतिक आपदाओं की बात आती है, तो बाद, तूफान, या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाओं की तुलना में भूकंप का नाम सबसे अनिश्चित और निराशकारी रूप में सामने आता है। इसका कारण यह है कि विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी हम भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं। यद्यपि वैज्ञानिकों ने उन क्षेत्रों की पहचान करने में सफलता प्राप्त की है जहां भूकंप का खतरा अधिक होता है और जहां भविष्य में भी इसकी संभावना बनी रहती है, फिर भी यह अनिश्चितता मानव जीवन और संपत्ति के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है।

भूकंप पृथ्वी की सतह पर होने वाली वह हलचल है जो इसके भीतरी भाग में संचित ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के आपसी टकराव, खिसकने, या दबाव के कारण पैदा होती है। पृथ्वी की ऊपरी परत, जिसे भूपर्पटी (क्रस्ट) कहते हैं, कई विशाल प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा (लावा) पर तैरती रहती हैं और निरंतर गति में रहती हैं। जब ये प्लेटें एक-दूसरे के खिलाफ रगड़ खाती हैं, दबाव बनता है, और यह दबाव जब अस्थायी हो जाता है, तो यह ऊर्जा भूकंपीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। यही तरंगें भूकंप का कारण बनती हैं। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल या मरकेली स्केल जैसे पैमानों से मापा जाता है। रिक्टर स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापती है, जबकि मरकेली

स्केल इसके प्रभाव को। उदाहरण के लिए, 2.0 से कम तीव्रता का भूकंप आमतौर पर महसूस नहीं होता, लेकिन 7.0 से अधिक तीव्रता का भूकंप व्यापक विनाश का कारण बन सकता है।

हालांकि भूकंप की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन क्षेत्रों की पहचान कर ली है जहां भूकंप की संभावना अधिक होती है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाओं के पास स्थित होते हैं। उदाहरण के लिए, 'रिंग ऑफ फायर' प्रशांत महासागर के आसपास का एक ऐसा क्षेत्र है जहां विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं। जापान, इंडोनेशिया, चिली, और पश्चिमी अमेरिका जैसे क्षेत्र इस रिंग का हिस्सा हैं। भारत में हिमालय क्षेत्र, कच्छ, और पूर्वी राज्य भूकंप के लिए संवेदनशील माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव होता है। इन क्षेत्रों की पहचान भूकंपीय इतिहास, भूगर्भीय संरचना, और प्लेट गति के अध्ययन के आधार पर की जाती है। फिर भी, यह अनुमान केवल संभावना को दर्शाता है, न कि निश्चित समय या तारीख को।

भूकंप के प्रभाव इसकी तीव्रता, गहराई, और प्रभावित क्षेत्र की जनसंख्या के घनत्व पर निर्भर करते हैं। एक शक्तिशाली भूकंप इमारतों को ढहा सकता है, सड़कों को तोड़ सकता है, और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा, भूकंप के बाद आने वाली सुनामी, भूस्खलन, और आग जैसी द्वितीयक आपदाएं स्थिति को और भयावह बना देती हैं। उदाहरण के लिए, 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप और उसके बाद की सुनामी ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। इसी तरह, 2011 में जापान में आए भूकंप ने न केवल भारी तबाही मचाई, बल्कि फुकुशिमा परमाणु संयंत्र में दुर्घटना का कारण भी बना। भारत में 2001 का कच्छ के भुज में आया भूकंप एक ऐसा उदाहरण है जिसने हजारों लोगों की जान ली और पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया।



मानव जीवन के अलावा, भूकंप का अर्थिक प्रभाव भी गहरा होता है। पुनर्निर्माण, राहत कार्य, और प्रभावित लोगों के पुनर्वास में अरबों रुपये खर्च होते हैं। विकासशील देशों में यह बोलझ और भी भारी हो जाना है, जहां संसाधन पहले से ही सीमित होते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी की असंभवता का कारण पृथ्वी के भीतरी भाग की जटिलता और उस तक सीमित पहुंच है। वैज्ञानिक भूकंपीय तरंगों, प्लेट गति, और भूकंपीय तनाव का अध्ययन करते हैं, लेकिन ये संकेत इतने सूक्ष्म और अनियमित होते हैं कि इनके आधार पर सटीक समय और स्थान का अनुमान लगाना असंभव हो जाता है। कुछ जानवरों, जैसे कुत्ते और पक्षी, के व्यवहार में परिवर्तन को भूकंप से जोड़ा गया है, लेकिन यह भी कोई विश्वसनीय तरीका नहीं है और आज मनुष्य मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया तो पशुओं के व्यवहार का अध्ययन इतना सरल कैसे हो सकता है? वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग भूकंपीय डेटा के विश्लेषण के लिए किया जा रहा है। ये तकनीकें पैटर्न की पहचान कर सकती हैं, लेकिन अभी तक ये केवल जोखिम वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने तक सीमित हैं, न कि सटीक भविष्यवाणी करने में।

भूकंप की भविष्यवाणी न कर पाने की स्थिति में सबसे प्रभावी रणनीति है तैयारी और बचाव। भूकंप प्रतिरोधी भवनों का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम है। जापान जैसे देशों

ने इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, जहां ऊंचे ऊंचे भवन लचीले ढांचे और उन्नत तकनीक के साथ बनाए जाते हैं ताकि वे भूकंपीय झटकों को सह सकें।

सर्वजनिक जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोगों को यह सिखाया जाना चाहिए कि भूकंप के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए—जैसे कि मेज के नीचे छिपना, खुली जगह में जाना और लिफ्ट का उपयोग न करना। स्कूलों और कार्यालयों में नियमित भूकंप अभ्यास (ड्रिल) आयोजित किए जाने चाहिए। सरकारों को भी आपदा प्रबंधन के लिए मजबूत नीतियां बनानी चाहिए। राहत सामग्री, चिकित्सा सुविधाएं, और बचाव दल पहले से तैयार रखे जाने चाहिए ताकि आपदा के बाद तुरंत कार्रवाई की जा सके। भूकंप न केवल एक प्राकृतिक आपदा है, बल्कि यह मानव सभ्यता के लिए एक सबक भी है। यह हमें प्रीति को शक्ति और हमारी समीतों की तक दिलाता है। जैसे-जैसे हमारी तकनीक और समझ बढ़ती है, हमें उम्मीद है कि भविष्य में हम भूकंप के प्रभाव को कम करने में और सक्षम होंगे। लेकिन तब तक, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा—सावधानी, तैयारी, और सामूहिक जिम्मेदारी के साथ। भूकंप एक ऐसी आपदा है जो अपनी अनिश्चितता के कारण भयावह बनी हुई है। फिर भी, विज्ञान और समाज के संयुक्त प्रयासों से हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं।

बलदेव राज भारतीय

पंजाब की अमन शान्ति को किसकी नजर?

पंजाब किसी समय में देश का सबसे अमन शान्ति, खुशहाली वाला राज्य हुआ करता था मगर अब मानो इससे किसी की नजर लग गई हो। पंजाब के लोगों ने कई बार संताप झेला, बावजूद इसके सभी लोग आपसी भाईचारे और प्यार भावना के साथ जीवन बसर करते, एक-दूसरे के दुख-दर्द को समझा करते मगर इस समय भाई ही भाई का बैरी होत जा रहा है। ज्यादातर युवा वर्ग नशा का आदी हो चुका है जो शायद इस माहौल के लिए सबसे अधिक जिम्मेवार है। नशा ना मिलने की स्थिति में लोग अक्सर चोरी, डकैती, हत्या तक की वारदात को अन्जाम दे देते हैं। दूसरा जिस प्रकार राजनीतिक लोगों ने अपने वोट बैंक की खातिर दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर पंजाब में बसाया जा रहा है इसमें बहुत से लोग आपराधिक प्रवृत्ति के भी रहते हैं जो यहां आकर वारदातों को अन्जाम दे रहे हैं। यहां तक कि गुरु की नगरी अमृतसर जहां शायद ही कभी इस तरह की वारदात होती देखी थी, आज सबसे अधिक क्राईम देखा जा रहा है। देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु रोजाना पहुंचते हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाता। अब इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है जो शायद पंजाब को प्रफुलित होता नहीं देख पा रही और उनकी पूरी कोशिश रहती है कि कैसे भी करके पंजाब में इस तरह का माहौल पैदा किया जाये। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तर्पण चुध की मानें तो पहले अकालियों और अब भगवंत मान सरकार की नाकामी के चलते पंजाब में कई तरह के माफिया कार्यरत हैं और उन्हें इनके ही कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त है। सबसे पहले उन पर काबू पाना होगा और उसके बाद नशे के कारोबार करने वालों पर लगाम कसनी होगी तभी पंजाब का माहौल ठीक किया जा सकता है। पंजाब में हिन्दू-सिख एकता में दरार डालने की भी पुनः कोशिशें की जा रही हैं उसे रोकना भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब फिर से काले दौर में वापिस लौट जाए। उस दौर में पंजाब को जो

नुक्सान हुआ उसकी भरपाई पंजाब
आज तक नहीं कर पाया है।

अकाली दल की भर्ती पर विवाद
बीते 2 दिसम्बर को श्री अकाल
तख्त साहिब से पांच जयध्वारां द्वारा
फैसला सुनाते हुए अकाली दल की
भर्ती को लेकर भी एक आदेश जारी
किया गया था जिसमें भर्ती के लिए
7 सदस्यीय टीम का गठन भी हुआ।
था मगर बाद में 2 सदस्यों के द्वारा
इस्तीफा दिये जाने के बाद केवल 5
सदस्य ही शेष रह गये। जब उन्होंने
भर्ती अभियान की शुरुआत की तो
सिख समुदाय के लोगों ने पूरी
दिलचस्पी के साथ स्वेच्छा से
सदस्यता ली है। इसके लिए 6 महीनों
का समय रखा गया है जिसके बाद
अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का
चयन किया जाएगा। मगर दूसरी ओर
श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों
को दरकिनार कर बादल परिवार की
छत्रछाया में भी भर्ती अभियान
चलाया जा रहा है जो शायद पहले
की तरह केवल कागज़ों तक सिमट
कर रह जाता है, क्योंकि वह चाहते
ही नहीं कि कोई आम सिख अकाली
दल का सदस्य बने। अगर ऐसा होता
है तो शायद सुखबीर सिंह बादल को
प्रधान बनाने की दिशा में बाधा आ
सकती है जो वह कभी नहीं चाहते।

भर्ती अभियान से पैदा हुए विवादों से आम सिख काफी आहत दिखाई दे रहा है क्योंकि आए दिन दोनों गुटों के द्वारा एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपने भर्ती अभियान को जायज ठहराया जा रहा है। अब तो यह भी उन्हीं कहा जा सकता कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार इसमें हस्ताक्षेप करें क्योंकि जथेदार की पदवी भी इनकी गुटबाजी की भेंट चढ़ चुकी है। बादल समर्थक गुट के द्वारा नए जथेदार की ताजपोशी भी शुरू की है मगर दूसरा गुट अभी भी ज्ञानी चुकबीर सिंह को श्री अकाल तख्त साहिब और ज्ञानी हरप्रीत सिंह को तख्त दमदमा साहिब का जथेदार मानकर सम्मान देते हैं। सिख बुद्धिजीवी कुलमोहन सिंह का मानना है कि आज वाले दिनों में यह विवाद और गहरा सकता है क्योंकि बादल समर्थक जल्द ही भर्ती कार्य



को पूरा कर सुखवीर सिंह बादल को पुनः प्रधान घोषित कर सकते हैं जिस दूसरा गुट कभी बदार्शत नहीं करेगा। दल पंथ, निहंग जथेबाँ?दयों, संत समाज का समर्थन आम गुट को प्राप्त है और वहीं उस सिख धर्म चाहता है कि परिवारवाद का खात्मा कर पंथक सोच वाली किसी धार्मिक शख्सियत को अब आगे आकर आकाश की दल की कमान संभालनी चाहिए जिससे अकाली दल की छवि फिर से बेहतर बनाई जा सके।

सिख पंथ की एकजुटता के लिए विचार

बीते दिनों न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं के साथ मुलाकात करने का अग्रिम मसलों पर विचार हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा न्यूजीलैंड में खालिस्तानी गतिविधियों पर चिन्ता जताते हुए उपर पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी अब न्यूजीलैंड के पूर्व मंत्री कंवलजीत सिंह बख्शी ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा से भेंट की दोनों नेताओं ने भारत और न्यूजीलैंड में सिख मसलों के समाधान एकजुटता बहाल करने और खालिस्तानी गतिविधियों को कैसे रोका जाए पर विचार हुए। बख्शी कंवलजीत सिंह ने चिन्ता व्यक्त की कि भारत में एक बार फिर से ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जिसमें सिख ही सिख का बरी बनता जा रहा है। सिख पंथ में बढ़ते टकराव का सामना सिख खासकर युवा वर्ग काफ़ी आहत होता है मगर शायद कुछ

ताकत हैं जो इसे तूल देकर विवाद को और बढ़ाने में कामयाब होती दिख रही हैं। बख्शी कवलजीत सिंह का समूचा परिवार हमेशा से ही कोमक की सेवा करता आ रहा है। उनके पिता बख्शी जगदेव सिंह के समय भी ऐसा माहौल बना हुआ था जिसके बाद उन्होंने एक नारा दिया था “जो सिख सिख नू ना मारे तो कोम कदे ना हारे” जिसे दिल्ली की हर दीवार पर लिखा गया था। शायद आज भी आवश्यकता है सिख पंथ की एकजुटता के लिए कोई आगे आए।

अच्छी पहल-डॉ. गुरमीत सिंह सूगर जो कि भाजपा के कदावर सिख नेता हैं जो मानते हैं कि प्रमाता से अगर उन्हें समर्थन बनाया है तो उन्हें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। इसी के चलते वह हर साल अपने जन्मदिन पर 5 बच्चों की पूरी पढ़ाई की जिम्मेवारी उठाते हैं। इस बार भी उनके द्वारा इसे जारी रखते हुए 5 ऐसे बच्चों का चयन कर उनकी पढ़ाई की जिम्मेवारी उठाई, जिनके माता-पिता बच्चों को बेहतर एजुकेशन दिलाने में असमर्थ थे। डा. गुरमीत सिंह मानते हैं कि ऐसा करके उन्हें खुशी मिलती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग धार्मिक स्थलों पर सोना, चांदी, हीरे जवाराहत चढ़ाते हैं, पर शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि भगवान की खुशी इसी में रहती है कि आप जरूरतमंदों के मददगार बनें। सोना-चांदी दान करके आपको कुछ समय की खुशी मिलती है मगर आपके द्वारा दिलाई गई एजुकेशन से ना जाने कितने परिवारों के घरों में खुशियां आ सकती हैं।

संपादकीय

शिक्षा का संकट- नींव को बचाने की जंग

जब शिक्षक गायब, तो ज्ञान का दीपक कौन जलाएगा?



कल्पना करें—एक बच्चा सुबह-सुबह स्कूल की ओर चल पड़ता है, कंधे पर बस्ता, मन में सपने और आँखों में चमक। लेकिन स्कूल पहुँचते ही उसका दिल टूट जाता है—दवाजे पर ताला, शिक्षक गायब, और चारों ओर सन्नाटा। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि मध्यप्रदेश के उमरिया जिले की हकीकत है, जो हाल ही में कलेक्टर के औचक निरीक्षण में सामने आई। शिक्षा किसी भी समाज की रीढ़ होती है, लेकिन जब यह रीढ़ लापरवाही की मार से कमजोर पड़ने लगे, तो क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? उमरिया की यह घटना सिर्फ एक जिले का दर्द नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र के लिए एक जोरदार चेतावनी है। जब उमरिया के कलेक्टर ने सरकारी स्कूलों का औचक दौरा किया, तो जो देखा, वह दिल दहला देने वाला था। कहीं शिक्षक बिना बताए गायब थे, तो कहीं स्कूलों के दवाजे बन्द थे, लिए बंद मिले। यह सिर्फ ड्यूटी से चूक नहीं, बल्कि उन मासूम सपनों के साथ विश्वासघात था, जो हर बच्चा स्कूल लेकर आता है। कलेक्टर ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया—दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया और 29 की वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई। यह सख्ती जरूरी

थी, लेकिन क्या यह समस्या सिर्फ अमरिया की है? मध्यप्रदेश के हर कोने में अगर झाँके, तो यह लापरवाही एक गहरे संकट की ओर इशारा करती है। मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों को चमका देने के लिए सरकार ने ढेरों योजनाएँ शुरू कीं—नई इमारतें, मुफ्त किताबें, मिड-डे मील। लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है, तो सारा ढाँचा खोखला नजर आता है। शिक्षक समय पर नहीं आते, स्कूल प्रबंधन समय रहता है, और शिक्षा विभाग की निगरानी बस कागजों तक सीमित है। प्रवेश उत्सव जैसे आयोजन, जो बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए होते हैं, महज औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। नतीजा सामने है—अबच्चों की उपस्थिति गिर रही है, ड्रॉपआउट की दर बढ़ रही है, और शिक्षा की गुणवत्ता

धूल चाट रही है। योजनाएँ तो हैं, पर जब तक शिक्षकों और प्रशासन की जवाबदेही तय नहीं होगी, ये सब बेकार हैं। एक पल को रुकें और सोचें—वह बच्चा जो स्कूल के लिए मीलों पैदल चलता है, धूप-धूल में अपने सपनों को साँघता है, उसे क्या मिलता है? एक खाली कक्षा, एक अनुपस्थित शिक्षक और टूटती उम्मीदें। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों पर ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे निर्भर हैं। उनके लिए, स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि जिवंदी बदलने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन जब शिक्षक ही अपनी जिम्मेदारी से मुँह मोड़ लें, तो ये बच्चे कहाँ जाएँ? यह सिर्फ शिक्षा का संकट नहीं, बल्कि लाखों मासूमों के भविष्य पर लगा ग्रहण है। हर गायब शिक्षक के साथ एक बच्चे का सपना मरता है—क्या हम इसे यूँ ही देखते रहेंगे?

अगर मध्यप्रदेश की शिक्षा को बचाना है, तो अब नरमी नहीं, सख्ती चाहिए। उमरिया में हुई कार्रवाई इसकी मिसाल है—जब कड़ा कदम उठाया गया, तो संदेश साफ गया कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन यह काफी नहीं है। हर जिले में नियमित औचक निरीक्षण होने चाहिए। डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम से शिक्षकों की उपस्थिति पर नजर रखी जा सकती है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाएँ—साफ पानी, शौचालय, बिजली—को अनिवार्य करना होगा। साथ ही, शिक्षकों को न सिर्फ सजा, बल्कि बेहतर प्रशिक्षण और प्रोत्साहन भी देना होगा, ताकि वे ड्यूटी को बोझ नहीं, बल्कि जुनून समझें। यह सिर्फ नियम लागू करने की बात नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को

प्राथमिकता देने का वादा है। उमरिया
 की यह कार्रवाई एक चिंगारी है, जो पूरे
 प्रदेश में बदलाव की आग जला सकती
 है। अगर हर जिले में ऐसी सख्ती और
 पारदर्शिता आए, तो सरकारी स्कूल
 फिर से ज्ञान के मंदिर बन सकते हैं।
 यह सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है,
 बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है।
 हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई
 भी बच्चा स्कूल से खाली हाथ न लौटे।
 उमरिया ने एक मॉडल पेश किया है।
 अब इसे पूरे मध्यप्रदेश में लागू करने
 का वक़्त है। जब हर स्कूल में शिक्षक
 मौजूद हों, हर कक्षा में ज्ञान की रोशनी
 हो, तभी हम कह सकेंगे कि हमने
 अपनी नींव बचा ली।

शिक्षा महज किताबों के पन्ने पलटना नहीं, बल्कि हर बच्चे के मन में छिपे सपनों को पंख देना है—उन सपनों को, जो आसमान छूने की हिम्मत रखते हैं। उमरिया की घटना ने हमें नौद से झटका देकर जगाया है—अब आँखें मुँद रहने का वक्त नहीं, बल्कि उठ खड़े होने का समय है। सख्त अनुशासन की डोर, निगरानी का मजबूत जाल और बच्चों को दिल से प्राथमिकता देकर उठाया गया हर कदम इस डूबते तंत्र को बचा सकता है। आइए, आज एक पक्का इरादा करें—

हर बच्चे को वह शिक्षा दें, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो उसके सपनों को हकीकत में बदल सके। क्योंकि जब शिक्षा का किला अडिग होगा, तभी मध्यप्रदेश का भविष्य सन्तुष्ट हो सकेगा। यह एक जुनून नहीं पुरकार है—शिक्षा को जिंदा रखें, बच्चों के सपनों को उड़ने दें।

प्रो. आरके जैन

जन-गण-मन, अधिनायक जय हे

हमारे राष्ट्रगान की उक्त पंक्तियों को मैं कभी नहीं भूलता, क्योंकि इसमें भारतीय जनतंत्र की, भारतीय गणतंत्र, की और भारतीय मानसिकता की जय के साथ-साथ उस अधिनायक की भी जय बोली गयी है जो अदृश्य है। भारतीय जनतंत्र और गणतंत्र के बीच छिपकर बैठ ये अधिनायक हमेशा बहुमत के रूप में हमारे सामने प्रकट होता रहता है। इसका चेहरा कभी स्त्री का होता है तो कभी पुरुष का और कभी अर्धनारीश्वर का। अधिनायक की पहचान अक्सर संसद में किसी विधेयक पर मत विभाजन के समय होती है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 पर मत विभाजन के समय भी ये अधिनायकत्व खुलकर सामने आया है।

वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों पर मौजूदा सरकार की नजर शुरू से थी लेकिन उसने कोई मौक़ा नहीं मिल रहा था, किन्तु हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में मिली जीत ने बैशाखी सरकारों को इतना हौसला दिया कि वो मुसलमानों की टोपी ज़मकर उछले। सरकार ने ऐसा किया भी। वक्फ बोर्ड क्रानून में संशोधन कर अपने लिए बोर्ड में चुपपैठ करने की गुंजायश निकाल दी दब्डू। पूरा विपक्ष मिलकर भी इसे रोक नहीं पाया। रोक भी नहीं सकता था क्योंकि संख्या बल उसके पास नहीं था। अब ये विधेयक राज्यसभा में भी आसानी से पारित होने के बाद क्रानून का रूप ले लेगा। अब विपक्ष इसे न कानून बनने से रोक सकता है और न इस पर अमल करने से।

लोकसभा में इस विवादस्पद विधेयक पर पूरे 12 घंटे बहस चली। मुमकिन है कि आप में से बहुत कुछ ने ये पूरी बहस देखी हो, लेकिन मैंने इसे पूरा देखा, सुना। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सत्ता के लालच में टीडीपी और जेडीयू जैसे क्षत्रिय धर्मनिरपेक्ष दलों ने जहाँ अपना दीन-ईमान बेच दिया वहीं उड़बूट ठाकरे की शिव सेना और तुमलूल गिरेस और समाजवादी पार्टी जैसे लोग बिना लाभ-हानि की फ़िक्र किये विधेयक के विरोध में डटे रहे। अब पूरी मोदी सेना विपक्षी सांसदों को काफ़िर ठहराने पर लगी है। यानी मुसलमानों का समर्थन करना काफ़िर होना है और विरोध करना

सनातनी होना है।

भारत की आजादी के पहले के और बाद के इतिहास में किसी एक विरादरी के साथ इस तरह के दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव कभी नहीं हुआ। मुग़लों के जमाने में तो ऐसे बर्ताव का स्वागत ही नहीं उठता लेकिन अंग्रेजों ने भी ये ज़ुर्त नहीं की जो आज की जा रही है। सरकार की रीती, नीति और कार्यक्रम न जाने क्यों अचानक मुसलमान विरोधी हो गए हैं। सरकार अपने कार्यक्रमों और नीतियों के जरिये मुसलमानों को मुसलमान बना देने पर अमादा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। सरकार के मुस्लिम विरोधी रवैये से मुसलमान को अपने शुभचिंतक चुनने में पहले के मुकाबले ज्यादा आसानी होगी।

अभी तक राजनीतिक दलों पर मुसलमानों को तुष्ट करने का आरोप लगाता किन्तु अब मुसलमानों के हाथ में ये मौक़ा आया है की वे अपनी पसंद के राजनीतिक दलों को तुष्ट और पुष्ट करें। मुसलमान किस दल के साथ रहना चाहते हैं ये तय करने वाले हम और आप कोई नहीं हैं किन्तु हम लोकतंत्र में अधिनायक की पहचान में सबकी मदद कर सकते है। मुसलमानों की भी और हिन्दुओं की भी। आज से पचास साल पहले हम और इशाक भाई एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे,खाते थे,खेलते थे। हमारी माँ और फ़रीदा बेगम में बहुत फर्क नहीं था। दोनों के आंचल की छाव एक जैसी थी, लेकिन अब सब बदल चुका है। न इशाक हमारे साथ और न फ़रीदा बेगम। सियासत ने सभी को परया बना दिया है। कोई डर की वजह से परया हुआ है तो कोई सियासत की वजह से।

संख्या बल के चलते वक्फ बोर्ड विधेयक राज्यसभा में भी आसानी से पारित होगा, इसलिए वहां इस विधेयक पर बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बहुमत के बूटों से अविजयत का कुचला जाना अकालित्य के लोगों की नियति बन चुकी है। फिर भी उम्मीद है कि बी.भारत में जैसे हिलमिलकर हम सब रहते थे वैसे ही आगे भी रहेंगे। नहीं रहेंगे तो सब बर्बाद हो जायेंगे। हमारा भी वही हाल होगा जो किसी जमाने में महाराणा प्रताप का हुआ, छसपति शिवाजी का हुआ।

छतरसाल का हुआ, लक्ष्मीबाई का हुआ।
बंदा हुआ समाज कभी देश की ताकत
नहीं हो सकता। बंधी हुईं मुठ्ठी ही लाख
की होती हैं, खुल गयी तो हैं और लाख
की हो जाती हैं। मैं न काफिर हूँ, मुँह न
मुसलमान, लेकिन मैं भी उसी तरह
सनातनी भारतीय हूँ जिस तरह इस देश
के सनातनी मुसलमान हैं। उनका भाग्य
बैशाखा लगाकर सरकार चलने वाले तय
नहीं कर सकते। किन्तु दुभाग्य है कि वे
ऐसा कर रहे हैं।

ऐसे मौकों पर मुझे 'मेरे महबूब फिल्म का वो गीत अक्सर याद आता है जिसे शकील बदाम्नी ने लिखा था। -कोई देखे ना देखे, अल्लाह दे रहा है।' हमारी सरकार अल्लाह की सरकार नहीं है। वो राममजी की सरकार है इसलिए अल्लाह से उठती नहीं है। उसके लिए ईश्वर, अल्लाह तेरो ही नाम नहीं है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक से हमारा कुछ बनना और बिगड़ना नहीं है। जिनका बचना और बिगड़ना है, उन्हें तय करना है कि वे इस मसले पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया दें। उनके सामने दोनों विकल्प हैं। वे चाहें तो सरकार के सामने घुटने टेकें और न चाहें तो सरकार को घुटे टेकने पर विवश करें। सरकार को न अदालत रोक सकती है और न अल्ला। सरकार को केवल और केवल वोट रोक सकता है। जो वोट की ताकत नहीं जानते, वे कुछ नहीं जानते।

इस देश में रामजी की सरकार कभी हिन्दू मंदिरों के न्यासों के घघलों के बारे में कभी गंभीर नहीं हो सकती। कभी ये नहीं कहते वाला कि सौ साल पहले हिन्दू मंदिरों की आय कितनी थी और आज कितनी है। सौ साल पहले हिन्दू मंदिरों की सम्पत्ति कितनी थी और आज कितनी है? ये सरकार कभी ये देखना और जानना या रोकना पसंद नहीं करेगी कि हिन्दू मंदिरों के ट्रस्टों की आड़ में देश के राज-महाराजाओं ने अपनी कितनी सम्पत्ति कराराधन से बचा रखा है ? अकेले व्वालिथर में एक ही राज परिवार के 19 ट्रस्ट इसी तरह से सत्तजोरी के धधे में लगे हैं। हर अनंत, हर कथा अनंत।

રાકેશ અચલ



**प्रधान
ग्रा०पं०-उफरौली
दरियाबाद, बाराबं**

